

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 202] नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 15, 2014/आषाढ़ 24, 1936 No. 202] NEW DELHI, TUESDAY, JULY 15, 2014/ASHADHA 24, 1936

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

अधिसूचना

मुंबई, 11 जुलाई, 2014

सं.टीएएमपी/61/2009-केपीटी.—महापत्तन न्यास अधिनियम 1963 (1963 का 38) की धारा 48, 49 और 50 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण एतद्द्वारा, कांडला पत्तन न्यास के प्रचलित दरमान की वैधता को, संलग्न आदेशानुसार विस्तार प्रदान करता है।

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण प्रकरण सं. टीएएमपी/61/2009-केपीटी गणपूर्ति

- (i) श्री टी.एस. बालासुब्रमणियन्, सदस्य (वित्त)
- (ii) श्री चंद्रभान सिंह, सदस्य (आर्थिक)

आदेश

(जुलाई 2014 के 4 थे दिन पारित)

यह आदेश कांडला पत्तन न्यास (केपीटी) के प्रचलित दरमान को विस्तार प्रदान करने से संबंधित है।

2. केपीटी का प्रचलित दरमान (एसओआर) इस प्राधिकरण द्वारा पिछली बार आदेश सं. टीएएमपी/61/2009-केपीटी, दिनांक 18 जनवरी 2011 के माध्यम से अनुमोदित किया गया था जो भारत का राजपत्र में 22 फरवरी 2011 को अधिसूचित किया गया था। यह आदेश, दरमान की वैधता 31 मार्च 2013 तक प्रदान करता है। इस प्राधिकरण ने केपीटी के

2880 GI/2014 (1)

दरमान की वैधता को दो बार विस्तार प्रदान किया था और अंतिम बार दिनांक 4 अप्रैल 2014 के आदेश के जरिए 30 जून 2014 तक, विस्तार प्रदान किया है।

- 3.1. दरमान के संशोधन हेतु केपीटी द्वारा दिनांक 3 जनवरी 2013 के अपने पत्र के माध्यम से प्रस्तुत प्रस्ताव को एक प्रशुल्क प्रकरण के रूप में पंजीकृत किया गया है और स्टेकधारकों के साथ परामर्श हेतु लिया गया है। अतिरिक्त जानकारी/ स्पष्टीकरण मांगते हुए एक विस्तृत प्रश्नावली 17 अप्रैल 2013 को पत्तन को जारी कर दी गई है। केपीटी ने, दिनांक 7 अगस्त 2013 के अपने पत्र के जरिए, बताया है कि वह वर्ष 2012-13 के वार्षिक लेखा के आधार पर लागत विवरणी को अद्यनित कर रहा है और व्यापार जगत की सहमति और बोर्ड का अनुमोदत प्राप्त करने के लिए कुछ और समय लग सकता है।
- 3.2. इसके बाद, केपीटी ने, दिनांक नवंबर 2013 के अपने पत्र के जिरए, अन्य बातों के अलावा, बताया है कि पत्तन ने अपने प्रस्ताव को, 2012-13 के वित्त परिणामों को अद्यनित करते हुए, दोबारा तैयार किया है और परामर्श हेतु उपयोक्ताओं को परिपत्रित किया है। बोर्ड की आगामी बैठक में, अपने बोर्ड का अनुमोदन मांगने के बाद, केपीटी ने अपने संशोधित प्रस्ताव को दाखिल करने के लिए सहमित व्यक्त की थी। इस कारण पत्तन ने इस प्रकरण को बंद नहीं करने का अनुरोध किया है।
- 3.3. केपीटी के अनुरोध को ध्यान में रखते हुए, इस प्राधिकरण ने निर्णय लिया है कि केपीटी को अपने प्रस्ताव दाखिल करने के लिए 15 फरवरी 2014 तक समय दिया जाए।
- 4. अब केपीटी ने दिनांक 16 मई 2014 के अपने पत्र के माध्यम से, 24 मार्च 2014 को ली गई अपने बोर्ड की बैठक का कार्यवृत्त संलग्न करते हुए इस प्राधिकरण से अनुरोध किया है कि इसके दरमान के संशोधन हेतु (प्रस्तुत) इसके प्रस्ताव को आस्थगित रखें और साथ ही अनुरोध किया है कि इसके प्रचलित दरमान की वैधता को विस्तार प्रदान किया जाए।
- 5.1. इसके दरमान के संशोधन प्रस्ताव आस्थगित करने के लिए केपीटी के अनुरोध के संदर्भ में, इस प्राधिकरण ने एक पृथक आदेश सं. टीएएमपी/73/2012-केपीटी दिनांक 4 जुलाई 2014 को पारित किया है।
- 5.2. इसी बीच, केपीटी के प्रचलित दरमानों की विस्तारित वैधता 30 जून 2014 समाप्त हो चुकी है। इस तथ्य पर विचार करते हुए कि केपीटी द्वारा अपना प्रस्ताव दाखिल किया जाना बाकी है, केपीटी के प्रचलित दरमान को 30 जून 2014 के आगे (की अविध हेतु), केपीटी के अनुरुष के अनुरूप, विस्तार प्रदान करना आवश्यक है। अतएव, यह प्राधिकरण, केपीटी के प्रचलित दरमान की वैधता को, इसकी वैधता की समाप्ति की तिथि से 30 सितंबर 2014 तक अथवा संशोधित दरमान के क्रियान्वयन की प्रभावी तिथि तक, इनमें से जो भी पहले हो, विस्तार प्रदान करता है।
- 5.3. 1 अप्रैल 2013 के बाद वाली अविध में ग्राह्य लागत और अनुमेय प्रतिलाभ से अधिक कोई अतिरिक्त अधिशेष उभरता है तो, उसकी निष्पादनता की समीक्षा के समय, वह अतिरिक्त अधिशेष निर्धारित किए जाने वाले प्रशुल्क में, पूर्णतः समायोजित किया जाएगा।

टी.एस. बालासुब्रमणियन, सदस्य (वित्त)

[विज्ञापन III/4/असा./143/2014]

TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS NOTIFICATION

Mumbai, the 11th July, 2014

No. TAMP/61/2009-KPT.—In exercise of the powers conferred under Sections 48, 49 and 50 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Tariff Authority for Major Ports hereby extends the validity of the existing Scale of Rates of the Kandla Port Trust as in the Order appended hereto.

TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS

Case No.TAMP/61/2009-KPT

QUORUM

- (i) Shri T.S. Balasubramanian, Member (Finance)
- (ii) Shri Chandra Bhan Singh, Member (Economic)

ORDER

(Passed on this 4th day of July 2014)

This Order relates to the extension of the validity of the existing Scale of Rates of the Kandla Port Trust (KPT).

- 2. The existing Scale of Rates (SOR) of the KPT was last approved by this Authority *vide* Order No. TAMP/61/2009-KPT dated 18 January 2011 which was notified in the Gazette of India on 22 February 2011. The Order prescribes the validity of the SOR till 31 March 2013. This Authority has extended the validity of SOR of KPT on couple of occasions; the last being till 30 June 2014 *vide* Order dated 4 April 2014.
- 3.1. The proposal filed by the KPT *vide* its letter dated 3 January 2013 for revision of SOR is registered as tariff case and is taken on consultation with stakeholders. A detailed questionnaire has been issued to the port on 17 April 2013 seeking additional information/clarification. The KPT, *vide* its letter dated 7 August 2013, has submitted that it is updating the cost statements based on Annual Accounts for the year 2012-13 and it will take time for obtaining consent of the trade and approval of its Board.
- 3.2. Subsequently, the KPT, vide its letter dated 26 November 2013, *inter alia*, stated that the port has reformulated its proposal updating financial results of 2012-13 and circulated it to users for consultation. After seeking approval of its Board, the KPT had agreed to submit its revised proposal after seeking approval of its Board in the ensuing meeting. In view of that the port had requested not to close the case.
- 3.3. Considering the request of the KPT, this Authority decided to grant time till 15 February 2014 to KPT to file its proposal.
- 4. The KPT now, *vide* its letter dated 16 May 2014, while attaching the minutes of its Board Meeting held on 24 March, 2014, has requested this Authority to keep in abeyance its proposal for revision of its SOR and has simultaneously requested to extend the validity of its existing SOR.
- 5.1. With reference to the request of the KPT to keep in abeyance its proposal for revision of its SOR, this Authority has passed a separate Order No. TAMP/ 73/2012-KPT dated 04 July 2014.
- 5.2. In the meantime, the extended validity of the existing SOR of KPT expires on 30 June 2014. Considering the fact that the KPT is yet to file its revised proposal, the existing SOR of KPT needs to be extended beyond 30 June 2014 as requested by the KPT. This Authority, therefore, extends the validity of the existing SOR of KPT from the date of its expiry till 30 September 2014 or till the effective date of implementation of the revised Scale of Rates, whichever is earlier.
- 5.3. If any additional surplus over and above the admissible cost and permissible return emerges for the period post 1 April, 2013, during the review of its performance, such additional surplus will be set off fully in the tariff to be determined.

T.S. BALASUBRAMANIAN, Member (Finance) [ADVT. III/4/Exty./143/2014]